दिलाया गया कि भारत दक्षिण अफीका के लोगों को. उनके न्यायोचित संघर्ष में, बराबर समर्थन और सहायता देता रहेगा।

Written Answers

रूस के साथ व्यापार करार

7109. श्री रामावतार शास्त्री: क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्यायह सच है कि भारत तथा रूस के बीच एक नया व्यापार करार होने वाला है;
- (ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस करार को अन्तिम रूप देने में कुछ क ठिनाई हो रही है;
- (ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

बैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीराम सेवक): (क) जी हां।

- (स्त) जीनहीं।
- (ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते।

मारतीय यूरेनियम निगम को हानि

7110. श्री रामावतार शास्त्री: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 1968-69 में भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड को कितनी हानि हई;
 - (ख) उसके क्याकारण थे; और
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि निगम को घाटा न हो, सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्बिरा गान्धी) : (क) मूल्य-ह्रास के रूप में 62.22 लाख रुपये, उघार ली गयी राशि पर दिये जाने वाले ब्याज के लिए 36.88 लाख रूपये तथा खानों के विकास तथा मिल के चालु होने से पहले हुए खर्च को बट्टे खाते डालने के लिये 16.02 लाख रुपये की ब्यवस्था करने के बाद 70.51 लाख रुपये की हानि हुई।

- (ख) कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों को दूर करने के बाद जादगुडा यूरेनियम मिल ने मई. 1968 से व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करना शुरू किया । नवम्बर, 1968 में मिल पूरी क्षमता से काम करने लगी । इस कारण, पूर्ण तथा स्थिर उत्पादन का लाभ वर्ष 1968-69 में नहीं उठाया जा सका।
- (ग) संचालन-कायं अब नियमित रूप से चल रहा है तथा खान और मिल अब लगभग पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहे हैं परिणाम स्वरूप, यह आशाकी जाती है कि वर्ष 1969-70 में कम्पनी की आर्थिक उपलब्धियां ज्यादा अच्छी रहेंगी।

'क्लिट्ज' तथा 'सर्च लाइट' के नेपाल में प्रवेश पर प्रतिबन्ध

> 7111. श्री रामावतार शास्त्री: भी जार्ज फरनेन्द्रीज : भी नवल किशोर शर्मा: श्री जगेश्वर यादव : श्री देवेन सेन :

क्या वैवेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे किः

(क) क्यायह सच है कि नेपाल सरकार ने पटना से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के दैनिक 'सर्च-लाइट' तथा बम्बई से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' के नेपाल में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया है:

- (स्त) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; जौर
- (ग) इस पर सरकार की क्याप्रतिकिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी हां।

- (ख) हम समझते हैं कि नेपाल सरकार ने इन प्रकाशनों में छपे कतिपय लेखों को नेपाल के राजनीतिक तंत्रों और वहां के प्रमुख व्यक्तियों की आलोचना माना है। कार्रवाई नेपाल सरकार का पूर्णतः आन्तरिक मामला है।
- (ग) नेपालियों से यह बता दिया गया है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है और वे सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। उन्हें यह भी सूचित कर दिया गया था कि वे लेख भारत सरकार के विचारों को नहीं व्यक्त करते।

Inter-Ministerial Committee on Export of Iron Ore

7112. SHRI G. C. NAIK: Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

- (a) when was the High Level Inter-Ministerial Committee on Export of Iron Ore, constituted;
- (b) the names of the members of the Committee; and
- (c) the number of times it has met and what are its reports?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI RAM SEWAK): (a) An Inter-Ministerial Committee called the Iron Ore Export (Project) Committee, was set up in October, 1964.

- (b) A list of the present members of the Committee is attached.
- (c) The Iron Ore Export (Project) Committee has had 27 meetings so far, besides a number of informal meetings. This is a permanent Committee and was not to prepare any particular report. The Committee's main objective is to coordinate all the activities in relation to the implementation of the Long-Term Programme for the export of iron ore.

List of Members referred to in Part (b) above

 Chairman, Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd.

Chairman

 Chairman, National Minerals Development Corporation Ltd.

Member

,,

- Adviser (Industry and Minerals) Planning Commission.
- Joint Secretary concerned with development of iron ore mines—Department of Mines and Metals.
- Joint Secretary (Port and Transport) Department of Shipping and Transport.
- Joint Secretary concerned with H.E.C., M.A.M.C. and other Heavy Engineering Projects—Department of Industrial Development.
- Joint Secretary concerned with iron ore exports, Ministry of Foreign Trade.
- Director (Transport)— Railway Board.
- Director (Planning)— Railway Board.
- Director (Plan Finance)
 Ministry of Finance (Department of Expenditure).
- Director, National Mineral Development Corporation.